

प्रेषक

एन०एस०सी० न्यायालय,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सीमावे

अतिरिक्त सचिव,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक २६ दिसम्बर, २००७

विषय:-

मै० ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इण्डिया लि० को खसरा नम्बर-२३१ के अन्तर्गत ०.४७४ है० के स्थान पर १.६०८० है० भूमि कय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-४९ मूकय/१८(१)/२००७ दिनांक ९-१०-२००७ एवं शासनादेश संख्या-४९ मूकय(१)/१८(१)/२००७ दिनांक १८-१२-२००७ के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में खसरा नम्बर-२३१ के अन्तर्गत ०.४७४ है० क्षेत्रफल की स्वीकृति दी गयी है। इस खसरा नम्बर की कुल १.६०८० है० भूमि के कय की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि इकाई के लिए स्वीकृत की गयी कुल भूमि उपरोक्त शासनादेश में अनुमत्य क्षेत्रफल ९.७१६ है० से अधिक नहीं होगी।

२- कृपया उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

३- उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(एन०एस०सी० न्यायालय)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तार दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ३- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ४- श्री डी० कृष्णामोचारी, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट, मै० ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इण्डिया लि० वारी हाऊस ए०एस०सी० चौरा रोड, चेन्नई।
- ५- निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
- ६- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

२१
(रानोय बडोनी)
अधुसचिव।